during 1991-92 and 1992-93 (upto September, 1992);

(c) whether these automobile units resorted to retrenchement of labour during this period;

(d) if so, the number of workers effected and alternative arrangements of employment made for them; and

(e) the steps taken by Government to boost the automobile sector?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) (SMT. KRISHNA SHAI):

(a) In the year 1991-92 there has been a general fall in the production of automobile vehicles.

(b) The Production of figures for the year 1991-92 and 1992-93 (upto September) are as follows:—

		1991-92	1992-93 (upto Sept.)
1.	Medium & Heavy Commercial Veh.	85,143	31,937
2.	LCV	54,814	23.618
3.	Cars	1,65,303	71,766
4.	Jeeps	31,501	18,838
5.	Scooters	4,54,132	3,16,979
6.	Motorcycles	2,24,962	1,79,978
7.	Mopeds	8,77,310	1,92,661
8.	3-wheelers	43,813	31,125

(c) None of the automobile units has reported reternchement of labour.

(d) Does not arise.

(e) Government have since taken the remedial action of relaxation of import compression measures, reduction in excise duty on passenger cars and lowering of floor level rate of interest.

मध्य प्रदेश में विकास केन्द्रों की स्थापना

2717. श्री कैलाश नारायण सारंग: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के लिए छः विकास केन्द्र स्वीकृत किए हैं जिनमें प्रत्येक पर 30 करोड़ रुपये की लागत आएगी;

(ख) यदि हां, तो कितने विकास केन्द्रों के मामले में परियोजना प्रतिवेदनों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है तथा शेष विकास केन्द्रों के मामले में परियोजना प्रतिवेदनों को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की सम्भावना है

(ग) स्वीकृत परियोजना प्रतिवेदन वाले विकास केन्द्रों के मामले में सरकार और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा उन्हें देय राशि का ब्यौरा क्या है और उन्हें कितनी राशि पहले ही दी जा चुकी है तथा शेष राशि के कब तक दिए जाने की सम्भावना है,

(घ) क्या वित्तीय संस्थाओं को उनके अपने हिस्से की राशि जारी करने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस आशय के निर्देशों के कब तक जारी किए जाने की संभावना है तथा राशि कब तक स्वीकृत की जायेगी?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) विकास केन्द्र योजना योजना के अधीन आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में विकसित किये जाने हेतु मध्य प्रदेश को 6 विकास केन्द्र आवंटित किये गये हैं।

(ख) बोराई, चैनपुर, भिरोंगी खेड़ा और सिलतारा नामक 5 विकास केन्द्रों की परियोजना रिपोर्टों का अनुमोदन कर दिया गया है और सतलापुर की परियोजना रिपोर्ट मूल्यांकन के लिये भेज दी गयी

(ग) से (ङ) जिन 5 विकास केन्द्रों की परियोजना रिपोर्टें अनुमोदित हो चुकी हैं उनके लिए 8 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता दे दी

गयी है। प्रत्येक विकास केन्द्र के लिए 10 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता दी जाती है और यह सहायता राशि योजना के कार्यान्वयन की प्रगति के आधार पर किस्तों में दी जाती है। वित्तीय संस्थानों का अंशदान प्रति विकास केन्द्र 5 करोड़ रुपये होता है। इस कार्य के लिए केन्द्रीय एजेंसी के रूप में काम करने वाले भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के ब्यौरे तैयार करने का अनुरोध किया गया है और यह भी अनुरोध किया गया है कि कार्यान्वयनाधीन विकास केन्द्रों को अपना अंशदान देने लगे।

New agency to help entrepreneurs

2718. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the PRIME MINISTER be Pleased to state:

(a) Whether Government's attention has been drawn to a newsitem which appeared in the Economic Times dated 7th October, 1992 captioned "The red tape is alive and kicking";

(b) whether Government are aware of any study undertaken recently by the Confederation of Indian Industry according to which "an entrepreneur still faces 18 Agencies for clearance under the I.D.R. Act" and confronted by "51 inspectors" dealing with industrial laws apart from difficulties in getting funds, clearance from DGTD, CCI &E, Pollution Control Board, excise duties etc; and

(c) if so, whether Government propose to set up some institution or agency which could provide the base line data all over the country with a veiw to save those entrepreneurs who are relatively small in terms of investment or capacity etc.?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) (SMT. KRISHNA SAHI): (a) and (b) Yes Sir. The Government is aware of the Newsitem in the Economic Times and the study undertaken by the Confederation of Indian Industry.

(c) All clearances under the provision of I (D&R) Act, are given by the Secretariat for Industrial Approvals in the Ministry of Industry. Subsequent to the announcement of new Industrial Policy, procedures for according approvals have been substantially simplified. A Facilitation Cell has been set up in the Ministry of Industry to provide information to the entrepreneurs on Licensing Policy, tariffs and duties, corporate taxation and company law matters.

राजस्थान में उद्योगों की स्थापना

2719. **श्री मूलचन्द मीणा:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान उद्योगों के स्थापित किए जाने संबंधी कितने प्रस्ताव राजस्थान से प्राप्त हुए है;

(ख) इनमें से कितने प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया और कितने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिये; और

(ग) इन प्रस्तावों के अस्वीकार कर दिये जाने के क्या कारण थे?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) और (ख) निम्नलिखित तालिका से पता चलता है कि राजस्थान में उद्योगों की स्थापनार्थ औद्योगिक लाइसेंस, हेतु 1991 और 1992 (नवम्बर तक) के दौरान कितने आवेदन मिले:-

	1991	1992 (नवम्बर तक)
(1) प्राप्त आवेदनों की संख्या	104	15
(2) अनुमोदित	14	9
(3) अस्वीकृत	33	1
(4) लाइसेंस आवश्यक नहीं था/आवेदन वापिस ले लिये गये	44	—

(ग) आवेदन मुख्यतया क्षमता संबंधी अड़चनों,